जनसत्ता

दागियों का दबदबा

इस बार भी दागी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई, नतीजतन लोकसभा चुनाव में खासी तादाद में ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं तक राजनीति के इस अपराधीकरण को रोक पाने में एक तरह से बेबस साबित हुई हैं। हालांकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को लेकर इन दोनों ही संस्थाओं ने राजनीतिक दलों को कसने की काफी कोशिशें कीं, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों की अनदेखी से इन संस्थाओं के प्रयास विफल ही रहे हैं। इतना जरूर हुआ है कि लोग अब समझने लगे हैं कि अगर ऐसे दागी नेताओं को वोट देंगे तो आने वाले वक्त में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी! दागी नेताओं को लेकर सर्वोच्च अदालत ने समय-समय पर जो आदेश दिए हैं, उनसे आम जनता के बीच बड़ा संदेश तो गया है और लोग वोट डालने से पहले उम्मीदवार के बारे में विचार जरूर कर रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा तो ऐसे दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने का है।

मतदाताओं के सामने समस्या यह होती है कि उम्मीदवार के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। खासतौर से उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में। इसी का फायदा उठा कर राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार देते हैं। ऐसे उम्मीदवार धन और बाहुबल की ताकत पर चुनाव लड़ते हैं और जनता के हितों, उससे जुड़े मुद्दों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। इस बार भी सियासी मैदान में दागी नेताओं की फेहरिस्त लंबी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले चरण के चुनाव में सत्रह फीसद दागी उम्मीदवार मैदान में थे, इनमें भी बारह फीसद उम्मीदवार ऐसे थे जिनके खिलाफ संगीन मामले चल रहे हैं। हैरानी की बात यह कि इनमें से बारह उम्मीदवारों ने हलफनामे में बताया कि उन पर दोष साबित हो चुके हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है और महाराष्ट्र में चौवन ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं।

सवाल है जब हमारे जनप्रतिनिधि हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में लिप्त रहने वाले लोग होंगे तो उनसे देश किस तरह के भविष्य की उम्मीद करेगा। ऐसे दागी नेता सिर्फ जटिल और लंबी कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठा कर ही सदनों को सुशोभित करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे दागी नेताओं से बचा नहीं जा सकता। अगर राजनीतिक दल ठान लें तो ऐसे अपराधियों के लिए राजनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। पहली बात तो यह कि राजनीतिक दलों को नैतिक रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी उम्मीदवार को टिकट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल नैतिकता के मानदंडों को ताक पर रख देते हैं। वे इसी घातक प्रवृत्ति को अपनी कामयाबी की कुंजी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दागी नेताओं के मामले में सुनवाई के बाद यह व्यवस्था दी थी कि इस बारे में संसद को कानून बनाना चाहिए। लेकिन किसी भी दल ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। संसद में इस मुद्दे पर सारे दल एक साथ खड़े नजर आते हैं। राजनीति में शुचिता की बात करने वाले दलों को आखिर किस बात का डर है ऐसा कानून बन जाने से! अगर दागियों को राजनीति में आने से रोकना है तो इसके लिए राजनीतिक दलों को ही इच्छाशक्ति दिखानी होगी। वरना हमारे सदन अपराधियों का अड्डा ही नजर आएंगे। ऐसे में लोकतंत्र की मूल अवधारणा को किस स्तर की चोट पहुंचेगी, यह समझना मुश्किल नहीं है।

जानलेवा सड़कें

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुए बड़े सड़क हादसे ने एक बार फिर इस गहराती समस्या की ओर ध्यान दिलाया है कि सड़क और रफ्तार के असंतुलन की वजह से कितने लोग नाहक ही अपनी जान गंवाएंगे! शनिवार की रात आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली से वाराणसी जा रही एक बस और ट्रक की भयानक टक्कर में एक बच्ची सहित सात लोगों की मौत हो गई और करीब छत्तीस लोग बुरी तरह घायल हो गए। हो सकता है कि यह भी आए दिन होने वाले सड़क हादसों में शुमार कर लिया जाए, लेकिन क्या यह कोई अनदेखी करने लायक समस्या रह गई है? सच कहें तो सड़क पर रोजाना होने वाले हादसों और उनमें लोगों की मौत की घटनाओं को सामान्य सुरक्षा-इंतजाम और यातायात व्यवस्था में चौकसी और निगरानी के जरिए रोका जा सकता है। लेकिन अक्सर सड़कों पर वाहनों की छोटी या फिर बड़ी दुर्घटनाओं को भी सामान्य मान कर कागजी कार्रवाई और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं और फिर अगले किसी गंभीर हादसे के सामने आने तक के लिए शायद इसी प्रक्रिया का इंतजार किया जाता है!

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से एक्सप्रेस-वे पर लगातार हादसे और उनमें लोगों की मौत की खबरें आती रही हैं। आगरा-लखनऊ और दिल्ली-आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसे जिस रफ्तार से हो रहे हैं, वह अब चिंता की एक बड़ी वजह चुकी है। हाल ही में सूचना का अधिकार कानून के तहत सामने आई एक जानकारी के मुताबिक पिछले अठारह महीनों में लगभग दो हजार हादसे हुए, जिनमें करीब दो सौ लोगों की जान चली गई। आंकड़ों के मुताबिक एक्सप्रेस-वे पर हर रोज औसतन चार हादसे हुए और तीन दिन में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले साल लगभग डेढ़ सौ हादसे अकेले पशुओं के अचानक सड़क पर आ जाने से हुए। जबकि एक्सप्रेस-वे पर दोनों तरफ पशुओं को रोकने के लिए बाड़ लगी है। आगरा-दिल्ली एक्सप्रेस-वे की हालत इससे अलग नहीं है। आरटीआई से ही यह सामने आया कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर अगस्त 2012 से लेकर 31 मार्च, 2018 के बीच करीब पांच हजार हादसे हुए, जिनमें सात सौ से ज्यादा लोगों की जान चली गई और साढ़े सात हजार से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाल है कि इतनी तादाद में लगातार हादसों के बावजूद सरकार और संबंधित महकमे की नींद क्यों नहीं खुलती!

इन निर्बाध सड़कों पर हादसों की वजहों की पहचान भी हुई है। इनमें निर्धारित से काफी ज्यादा तेज गति से वाहन चलाना, गाड़ी चलाने के दौरान झपकी आना और कई बार अचानक पशुओं का सामने आ जाना मुख्य कारणों के रूप में दर्ज किए गए हैं। सवाल है कि इन चिह्नित कारणों के बावजूद इनके हल के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अगर एक्सप्रेस-वे पर वाहन की रफ्तार बेलगाम हो जाती है तो उन पर निगरानी या उन्हें रोकने के क्या इंतजाम हैं? पशु अचानक सड़क पर न आएं, इसके लिए बाड़ हैं। फिर वे कैसे सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के सामने आ जाते हैं? लंबी दूरी तक खुली सड़कें ड्राइवर के ध्यान को स्थिर, लेकिन शरीर और दिमाग को सुस्त बना सकती हैं। इस पहलू के हल के क्या किया जा रहा है? बहुत अच्छी सड़कें यातायात या आवाजाही को आसान और सुगम बना सकती हैं, लेकिन उन पर सुरक्षित सफर के लिए सबसे ज्यादा सावधानी बरतना वाहन चालक की ही जिम्मेदारी है। इसके बावजूद यातायात की व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए जरूरी है कि संबंधित महकमे हर इंतजाम और जरूरी होने पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि नाहक ही लोगों की जान जाने की घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

कल्पमेधा

कवि होने के बाद दूसरी महानता
है, कविता को समझना।
-लांगफेलो

बढ़ती आबादी, घटता पानी

सुविज्ञा जैन

इस समय भारत में बांधों और जल संचयन के दूसरे साधनों की संख्या और क्षमता दोनों ही जरूरत से बहुत पीछे हैं। देश में उपलब्ध पांच हजार से ज्यादा छोटे-बड़े बांध इस समय वर्षा से मिल रहे पानी को रोक कर रखने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जनसंख्या के आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत की जनसंख्या एक सौ छत्तीस करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले नौ साल में बाकी सभी देशों की तुलना करें तो भारत की जनसंख्या सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अभी भी चीन ही है, जिसकी आबादी इस समय एक सौ बयालीस करोड़ का आंकड़ा पार कर आई है। अगर चीन की जनसंख्या बढ़ोतरी की रफ्तार देखें तो पिछले नौ साल में वह सिर्फ 0.5 फीसद सालाना की दर से बढ़ी, जबकि इसी दौरान भारत की जनसंख्या 1.2 फीसद की दर से बढ़ी।

भारत में बढ़ती जनसंख्या के साथ संसाधनों की जरूरत भी बढ़ती है। हर देश के पास अपनी आबादी की गुजर बसर के लिए संसाधन सीमित होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन तो स्थिर होते हैं जिन्हें बढ़ाया ही नहीं जा सकता, जैसे- जल संसाधन। जल जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है और भारत इस समय अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी से जूझ रहा है तो वह पानी ही है। जिस रफ्तार से भारत की आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से पानी का इंतजाम करने में हम साल दर साल नाकाम होते जा रहे हैं। यह एक तथ्य है कि प्रचुर वर्षा के कारण कभी भारत जल संपन्न देश समझा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आबादी बढ़ने के कारण अब हम जल संपन्न देशों की सूची से बाहर हो गए हैं। यह अलग बात है कि इस भयावह हकीकत का पता हमें इसलिए नहीं चल रहा है कि हम पानी की जरूरत पूरी करने के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ाते आए हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि भूजल भी चुक जाने को आ गया है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है कि दो-तीन साल के भीतर ही देश के कई शहरों का भूजल स्तर हमारी पहुंच से नीचे गिर जाएगा।

इस समय विश्व में जितना भूजल निकाला जा रहा है उसका एक चौथाई यानी पच्चीस फीसद सिर्फ भारत निकाल रहा है। जबकि इस समय विश्व को प्रकृति से जितना ताजा पानी मिलता है उसमें भारत के हिस्से में सिर्फ चार फीसद आता है। संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजंसी फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन (एफएओ) के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कम से कम दो हजार घन मीटर पानी चाहिए। जिस देश में प्रति व्यक्ति इससे कम पानी उपलब्ध हो, उसे जल अभाव वाले देश की श्रेणी में रखा जाता है। अगर यह उपलब्धता एक हजार घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम हो तो उस देश को गंभीर जल अभाव की श्रेणी में रखा जाता है।

देश को आजादी मिलने के समय हमारी आबादी तैंतीस करोड़ थी और बारिश से हमें हर साल चार हजार अरब घन मीटर पानी मिलता था। तब प्रति व्यक्ति सालाना जल उपलब्धता पांच हजार छह सौ घन मीटर थी, यानी अंतरराष्ट्रीय मानदंड के लिहाज से पर्याप्त से कोई ढाई गुनी ज्यादा। लेकिन अब सन 2019 में हमारी आबादी एक अरब छत्तीस करोड़ हो चुकी है, यानी आजादी के बाद से आज तक आबादी चार गुना बढ़ गई। जबकि बारिश से मिलने वाले पानी की मात्रा वही है। इस तरह से इस वक्त भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की उपलब्धता लगभग एक हजार चार सौ घनमीटर ही बची है। लेकिन यह आंकड़ा उपलब्ध पानी का है, इस्तेमाल होने लायक पानी का नहीं। इसके लिए बारिश के पानी के सही-सही हिसाब-किताब पर गौर करना पड़ेगा।

भले ही देश की धरती पर वर्षा और हिमपात के रूप में चार हजार अरब घनमीटर पानी बरसता है, लेकिन यह पूरा का पूरा पानी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है। इस चार हजार अरब घनमीटर पानी में से आधे से ज्यादा यानी दो हजार एक सौ इकत्तीस घनमीटर पानी भाप बन कर उड़ जाने से और देश की विशिष्ट भू-आकृति के कारण इधर-उधर से बह कर समुद्र में चला जाता है। काफी कुछ पानी जमीन सोख लेती है। इसीलिए जल विज्ञानी हिसाब लगाते हैं कि सिर्फ एक हजार आठ सौ उनहत्तर अरब घनमीटर पानी हमें नदियों में और भूजल के पुनर्भरण के रूप में उपलब्ध है। लेकिन भारत की स्थलाकृति के कारण यह एक हजार आठ सौ उनहत्तर अरब घनमीटर पानी भी

पूरा का पूरा हमारी पहुंच में नहीं है। इस समय हमारी पहुंच सिर्फ एक हजार एक सौ तेईस अरब घनमीटर पानी तक है। इस आंकड़े में भी सतही जल सिर्फ छह सौ नब्बे अरब घनमीटर है। बाकी चार सौ तैंतीस अरब घनमीटर पानी भूजल के रूप में उपलब्ध है। बेशक यह भूजल एक प्रकार से वर्षा का ही पानी है जो रिस कर जमीन में जमा होता है, लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि बारिश का पानी जमीन में रिस कर कम मात्रा में जा रहा है और हम भूजल का दोहन ज्यादा कर रहे हैं।

दुनिया में सभी देश अपनी जल संचयन क्षमता बढ़ाने में लगे हैं। अमेरिका अपने हर नागरिक के लिए प्रति वर्ष पांच हजार घन मीटर जल का संचयन कर लेता है। मेक्सिको तक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एक हजार घन मीटर जल संचयन कर रहा है। जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना दो सौ पच्चीस घन मीटर पानी का ही संचयन हो पा रहा है। यह आंकड़ा भी औसत लेकर निकाला गया है। इस समय भारत में बांधों और जल संचयन के दूसरे साधनों की संख्या और क्षमता दोनों ही जरूरत से बहुत पीछे है। देश में उपलब्ध पांच हजार से ज्यादा छोटे-बड़े बांध इस समय वर्षा से मिल रहे पानी को रोक कर रखने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य पिछले साल के बारिश के आंकड़े हैं। पिछले साल सामान्य बारिश रहने के बावजूद कुछ ही महीनों के अंदर देश का सैंतालीस फीसद क्षेत्र सूखे की चपेट में आ गया था। सूखे के आंकड़े आइआइटी-गांधीनगर ने महीने भर पहले जारी किए हैं। मानसून के समय बाढ़ और कुछ ही महीनों बाद देश में सूखा पड़ जाना जल प्रबंधन की नाकामी का जीता जागता सबूत है।

पिछले साल ही नीति आयोग ने देश में पानी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि आने वाले दो-तीन साल में देश के इक्कीस शहरों का भूजल लगभग समाप्त हो जाएगा। इस समय सबसे ज्यादा भूजल का दोहन कृषि के लिए किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 2030 तक भारत में पानी की मांग आपूर्ति की तुलना में दुगनी हो चुकी होगी। अब जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से यह आफत 2030 के पहले भी आ सकती है।

हालत इतनी नाजुक है कि अगर किसी भी साल मौसम ने थोड़ी-सी भी ऊंच-नीच कर दी तो नतीजे कई गुने भयानक हो सकते हैं। वैसे यह अंदेशा इसी साल खड़ा हो गया है। पिछले हफ्ते ही यह बताया गया है कि इस साल अल नीनो प्रभाव के कारण भारत में बारिश सात फीसद कम होगी। उसके बाद सरकारी मौसम विभाग ने भी इस साल तीन फीसद कम बारिश का अनुमान लगाया है। जब देश का आधे से ज्यादा हिस्सा पहले से ही सूखे की चपेट में हो, बांध और जलाशय खाली पड़े हों, वैसी हालत में कम बारिश के अनुमान कुछ ज्यादा ही डरा रहे हैं। यह भी तय है कि पानी की कमी की समस्या अब साल दर साल और गंभीर होती जाएगी। अगर जल संचयन की क्षमता बढ़ाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता में न लाया गया तो बात हाथ से निकल जाएगी।

मेरा गांव मेरा देश

प्रेमपाल शर्मा

कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों के लिए लोकसभा का चुनाव था। सोचा, कुछ जायजा लिया जाए। जिला बुलंदशहर के निठारी गांव के एक जूनियर स्कूल में मतदान केंद्र था। निठारी नाम से कोई चौंक जा सकता है क्योंकि एक निठारी नोएडा में है तो एक यहां भी है। यों नोएडा के निठारी में जो हुआ था, वैसी करतूतें कई जगहों पर होती रही हैं। यानी बच्चों की नृशंस हत्याएं, विशेषकर गरीबों की। आपको पता होगा कि कैसे उन बच्चों के अंग निकाल कर नाले में उनके शव के बाकी हिस्से फेंक दिए जाते थे। निठारी के जिक्र के साथ इन दुखद स्मृतियों से नहीं बच सकते।

खैर, मैंने जिस निठारी की बात की, वहां मतदान केंद्र का स्कूल किसी भूत-बंगले की तरह दिख रहा था। धूल से अटे हुए कमरे। टूटी खिड़की। सिर्फ एक कमरे में पंखा लगा हुआ। मेज पर धूल, स्कूल की चारदिवारी भी ठीक-ठाक नहीं खींची हुई। मानो कोई पढ़ने के लिए आता ही नहीं हो। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों की यही स्थिति है। मैदान जरूर हैं, लेकिन धूल से भरे हुए। कोई छोटा-मोटा पेड़ भी नहीं। आखिर यह पेड़ सरकार लगाएगी तो उसकी छाया में केवल बच्चे नहीं, शिक्षक भी बैठ पाएंगे और उसकी ऑक्सीजन पूरे निठारी गांव तक फैलेगी। इस गांव में एक समर्थ, संपन्न और ताकतवर वर्ग की बहुलता है। वहां एक से एक बड़े पक्के मकान बने हुए हैं। बड़े-बड़े दरवाजे। कई-कई मंजिला घर देख कर कहीं से भी नहीं लगता कि यहां गरीबी है। गरीब है तो सरकारी स्कूल। निश्चित रूप से पास में कोई निजी स्कूल होगा, किसी चमचमाती इमारत में।

दुनिया मेरे आगे

खैर, उस दिन मतदान कराने वाली सरकारी टीम पहुंची। उसे स्कूल की इमारत को देख कर ज्यादा अचरज नहीं हुआ, क्योंकि टीम में सबके स्कूल ऐसे ही हैं शायद। यह उनकी आदत में शामिल हो गया है। उस टीम में महिला शिक्षक कर्मी भी थीं। मुझे लगा कि स्कूल की हालत और वहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव से उन्हें दिक्कत होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा अच्छा स्कूल है। इसके तो सामने ही मंदिर है! कितना सुंदर मंदिर है! मैं तो यहां आने से पहले दर्शन भी कर आई! उसमें भीतर बड़ी-बड़ी मूर्तियां हैं। संगमरमर का फर्श। खुशबू आ रही थी।' उनके साथ ही मौजूद एक अन्य महिला ने कोई टिप्पणी नहीं की। एक पुरुष ने कहा कि यहां का मंदिर मशहूर है! खुर्जा के पास भी एक और बड़ा काली माई का मंदिर है! आप उसे भी देख लीजिएगा।

इस बीच एक व्यक्ति ने बताया कि गांव के प्रधान वहां तशरीफ ला रहे हैं। वे एक सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्त हैं और फिलहाल इस गांव के प्रधान के रूप में जाने जाते हैं। क्या कभी इनकी नजर नहीं पड़ी होगी इस सरकारी स्कूल पर? क्या उनका ध्यान नहीं गया होगा कभी इस ओर कि स्कूल को मिलने वाला पैसा कहां जाता होगा? मेरा मन किया कि उनसे पूछूं, लेकिन डर था कि इस तरह के सवाल पूछने के बाद कहीं उन सबकी नाराजगी न झेलनी पड़े और उसे चुनाव से संबंधित गड़बड़ी न मान लिया जाए!

वहां जब मतदान शुरू हुआ तो मैं बाहर की तरफ निकल गया। दरवाजे पर कई तरह के लोग इकट्ठा हो रहे थे, तरह-तरह की बातें। शुरुआत करने वाले कुछ अतिरिक्त जोश से भरे हुए थे। मेरे यह कहते ही कि गांव तो बड़े पढ़े-लिखे हुए लोगों का लगता है, उनमें और उत्साह भर गया। हमारे गांव में रोबिन सिंह जूनियर टीम का खिलाड़ी है। उसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हमारे गांव के दो बच्चे कनाडा चले गए हैं और दिल्ली-कोलकाता में तो बीसियों रहते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। गांव से बाहर निकलने के रास्ते में एक जगह ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बज रहा था। सुबह-सुबह ही लगता है कोई शादी-विवाह का आयोजन था। वहां खड़े लोगों ने बताया कि यहां आज चौधरी साहब के बेटे की लगन है यानी सगाई। बहुत बड़ी पार्टी होनी है आज।

रुके हुए रास्ते का फायदा यह निकला कि कुछ और बातें भी हो गईं कि कैसे यहां सिर्फ यही मंदिर नहीं है और भी कई मंदिर आसपास जल्दी ही बने हैं। थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि दो बड़ी-बड़ी काली कारें खड़ी थीं। लेकिन उनकी आड़ में दो पुरुष बिना हिचक हंसते हुए खड़े-खड़े मूत्र त्याग कर रहे थे! यह है मेरे गांव में मेरे देश की तस्वीर। इनमें खूब पढ़े-लिखे और क्रिकेटर होने का फख्र है, कनाडा जाने का गर्व है, लेकिन न बदरंग स्कूल की इमारत पर शर्मिंदगी नहीं है और न सरेआम गली-गली को मूत्रालय-शौचालय बनाने की! देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन विचार के स्तर पर समाज एक ही जगह ठहरा हुआ लगता है। बदलाव का कोई अभियान जब तक मानसिकता बदलने पर केंद्रित नहीं होगा, उससे क्या बदलेगा?

रोजगार की खातिर

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के मुताबिक 2017-2018 में देश के ग्यारह राज्यों में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। इससे साफ है कि मांग के मुताबिक रोजगार का सृजन करने में हमारा देश विफल रहा है। हमारे यहां कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होते हैं। कृषि क्षेत्र में अल्प शिक्षित और अशिक्षित लोगों को मनरेगा के तहत कुछ महीनों के लिए ही रोजगार मिल पाता है लेकिन उसमें भी परिश्रम के हिसाब से आय बहुत कम होती है। छुपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में चरम पर है। विनिर्माण क्षेत्र उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहा हैं। मेक इन इंडिया जैसी कार्यक्रम हाशिये पर नजर पर आ रहे हैं। सेवा क्षेत्र प्रगति पर है लेकिन इसमें रोजगार के अवसर केवल प्रशिक्षित और उच्च शिक्षित लोगों को मिलते हैं। सरकारी नौकरियां महाराष्ट्र में अनुबंध के आधार पर निकाली जा रही हैं और केंद्र की नौकरियां उम्मीद के मुताबिक अब तक नहीं निकली हैं। राष्ट्रीय बैंकों में हर साल नौकरियां निकल रही हैं लेकिन घटते प्रतिशत में। देश के इंजीनियर अपने क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर न होने के कारण बैंक या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए मजबूर हो गए हैं।

दिन-प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं को कौशलभिमुख शिक्षा देने में अबतक विफल रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करके कौशल से संबधित शिक्षा को पर्याप्त जगह देनी चाहिए। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सटीक नीति बनाई जानी चाहिए और साथ ही मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अकुशल युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकें। कर्ज की प्रक्रिया सुलभ की जानी चाहिए ताकि तकनीक के बल पर सस्ती कीमत पर उत्पादन हो जो विदेशी उत्पादों को भी टक्कर दे पाए।

कृषि में कर्ज माफी की राजनीति से परे सोच कर सरकार को तकनीकी निवेश के सहारे कृषि को बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसान आत्मनिर्भर बन कर खेती कर पाएं। युवाओं को स्वरोजगार और उद्योग खोलने के लिए प्रेरित करने की खातिर ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र और कार्यशालाओं का प्रबंध करना चाहिए ताकि ग्रामीण युवाओं को कृषि के अलावा अन्य उद्योगों के बारे में जानकारी मिल सके। इस तरह के कदम उठा कर बेरोजगारी के समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली, महाराष्ट्र*

नेता बनाम जनता

हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी माननीयों के मुंह से सुविचार सुनने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान, सेना, साधु-संतों का श्राप, किसी खास पार्टी को वोट न देने पर लगने वाले करंट के झटके, उससे डरी हुई जनता और तमाशबीन बना चुनाव आयोग! गनीमत है कि इस देश में सब नेता हैं। नेता घर-घर में, चाय की दुकान में आपको मिल जाएंगे राष्ट्रीय दलों के ही नहीं, क्षेत्रीय दलों के भी। अब लठमार सिर्फ होली तक सीमित नहीं रहा, यह चुनावी चलन बन गया है। हिंदू-मुसलिम हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक का मुद्दा है। कुछ विदेशी पर्यवेक्षक 1950 से भविष्यवाणी करते आ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र संभव नहीं है पर भारत की जनता हर बार उनकी भविष्यवाणी पर पानी फेर देती है। चिंता तो होती है देश की राजनीति के हाल पर, क्या करें हम ऐसे ही हैं! कुछ दिनों में चुनाव खत्म होते ही नेता दिखेंगे नहीं और जनता अपने पुराने तेवर में बसों और ट्रेनों में लटक कर सफर करते हुए मुख्यधारा की दिनचर्या में मशगूल हो जाएगी!

● *सुमन कुमार सिंह, रांची, झारखंड*

जेट का संकट

करीब ढाई दशक पहले शुरू हुई भारतीय विमानन कंपनी जेट एयरवेज पर संकट गहराता चला गया और अंततः उसने अपनी सभी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। उसे यह कदम तब उठाना पड़ा जब ऋणदाताओं के समूह ने 400 करोड़ रुपए का कर्ज देने से मना कर दिया। पर इस सबके बीच बड़ा सवाल है कि विमानन उद्योग में हर साल चौबीस प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद यह संकट क्यों पैदा हुआ! केवल जेट नहीं बल्कि एअर इंडिया और विस्तारा जैसी कंपनियां भी बड़े वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं।

कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में सस्ते और आकर्षक किराए की होड़ भारतीय विमानन कंपनियों पर भारी पड़ रही है। ज्यादा उड़ानों के चलते सभी सीटें भरने के उद्देश्य से किराये में कटौती कंपनियों की मजबूरी हो गई है और यह उनकी कमर तोड़ दे रही है। ऊंची कीमतों पर मिलने वाला विमान का ईंधन और उस पर भारत में लगने वाला भारी भरकम कर भी कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर विमान कर्मचारियों का वेतन, उच्च एअर पोर्ट शुल्क, प्रबंधन द्वारा सही नियमन न होना आदि ऐसे कारण हैं जो विमानन कंपनियों को वित्तीय संकट में धकेल रहे हैं। अब सवाल है कि इसमें सरकार कहां खड़ी है! हम इनकार नहीं कर सकते कि बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, जो किया वह यात्रियों के लिए था। इसके मद्देनजर बढ़ते विमानन बाजार के आकार को सही दिशा देने के लिए एक ठोस और दूरदर्शी नीति की जरूरत है।

● *संजय दुबे, नई दिल्ली*

साझा रणनीति

श्रीलंका में जब 21 अप्रैल, ईस्टर के दिन लोग प्रभु यशु के पुनर्जन्म की प्रार्थना में व्यस्त थे उसी समय पूरे श्रीलंका में आठ स्थानों, जिनमें गिरजाघर और पांच सितारा होटल शामिल थे, आतंकी हमला किया गया। इसमें अब तक 290 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हैं। 1983 से 2009 तक गृहयुद्ध झेल चुके श्रीलंका में क्या फिर से आतंकवाद और अस्थिरता का दौर शुरू होने जा रहा है? इन 26 सालों में सेना, तमिल छापामारों और नागरिकों को मिला कर कोई डेढ़ लाख लोग मरे गए हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत 15 सौ शांति सैनिकों ने भी जान गंवाई। उस दौर के बारे में सोच कर भी सिहरन होने लगती है। लगभग हर महाद्वीप में आतंकी अपना जाल फैला चुके हैं। उनके खिलाफ विश्व के सभी देशों के एक मंच पर आना होगा और अपने सभी मतभेदों एवं मनभेदों को भुलाना होगा। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर साझा रणनीति बनानी पड़ेगा। केवल रस्मअदायगी या दो मिनट का मौन रख कर कुछ हासिल नहीं होगा।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com